world; and we have even declared the year 2001 as the Women's Empowerment Year and have taken up many programmes for the socio-economic empowerment of our women. One of the important programmes that we have in India is DWCRA, Self-help Groups. Out of seven lakh groups in the country, Andhra Pradesh alone has 4.12 lakh groups comprising 55 lakh women from Below the Poverty Line households. No State in India has such a huge number of women involved in such a successful Self-help Groups. But the support that we are extending to them is not sufficient. We have to take measures in regard to training and capacity building, technology and market support in order to sustain and strengthen them. There is also a need to extend insurance cover to all the members of the DWCRA Groups and whatever premium has to be paid to the insurance company has to be borne by the Central Government. The Government of Andhra Pradesh has started the DWMRA Scheme, a programme for the development of urban-poor minority community women. I request the Government for granting more financial assistance and extending insurance cover to this Group also. The Government of Andhra Pradesh is striving hard to create more and more Self-help Groups in order to empower the women and improve their economic condition. I would like to request the Central Government to release more funds for Andhra Pradesh in order to achieve the target of 14 per cent set by the Central Government by 2004. Thank you.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I would like to associate myself with this issue. Thank you.

Need to start special train from Jasideeh railway station and to provide Passenger Amenities

श्री अभय कांत प्रसाद (झारखंड) : उपसभापति महोदया, झारखंड में दिल्ली-हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर जसीडीह रेलवे स्टेशन है, इसके पास मन्दिर बाबा बैजनाथ धाम स्थित है । श्रावण मास मेले में प्रतिदिन लाखों कावंड़िया सुल्तानगंज से पैदल चल कर सैंकड़ों मील की दूरी तय कर बाबा बैजनाथ धाम मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में पूजा करने के पश्चात् देश के विभिन्न प्रदेशों को जाने के लिए जसीडीह रेलवे स्टेशन आते हैं, लेकिन इन यात्रियों के बैठने के लिए बड़े आकार का प्रतीक्षालय इस रेलवे स्टेशन पर नहीं है । रेलवे विभाग को श्रावण मास के इस मेले के कावंड़ियों से बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है । इस रेलवे स्टेशन पर आरक्षण का कोटा भी बहुत कम है तथा पर्याप्त मात्रा में गाड़ियां भी नहीं हैं ।अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रावण मास के मेले के लिए विशेष रेल गाड़ियां चलाई जाएं तथा सभी रेल गाड़ियों में यहां से आरक्षण

का कोटा बढ़ाया जाए । साथ ही जसीडीह रेलवे स्टेशन पर सफाई, बिजली, पानी, ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करने का कष्ट करें ।

Need for free transportation of potable water by railways for Rajasthan

श्रीमती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान): आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं आप के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राजस्थान में मानसून की बेरुखी ने किसानों को घायल कर दिया है । लगातार पिछले चार वर्षों से वर्षा के अभाव में बराबर अकाल पड़ रहा है जिस से प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति शोचनीय व दयनीय हो गई है । यहां तक कि पीने के पानी का अभाव हो गया है और प्रदेश में भू-जल का स्तर दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है । प्रदेश में एक बार हल्की-फुल्की वर्षा दो-चार जगह हुई जिस से किसानों ने जो बिजाई की थी, वह फसल भी सूखने की स्थिति में आ गई है और अब वह भी नष्ट हो जाएगी । इस कारण पशुधन को बचाना भी असंभव हो जाएगा ।

मैडम, राज्य में करीब-करीब 21 लाख परिवार ऐसे होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं । उन्हें और अधिक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ेगा । पिछले वर्षों में पेयजल उपलब्ध कराने में भारत सरकार ने रेलवे द्वारा पेयजल परिवहन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवायी थी, लेकिन इस वर्ष 21 जून को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार करेगी । मैडम, इस पेयजल व्यवस्था के लिए भी 125 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी जो कि राज्य सरकार के लिए असंभव है । राज्य सरकार की इस कठिनाई को सुलझाने हेतु केन्द्र सरकार को राजस्थान राज्य सरकार को उपरोक्त राशि का अनुदान देना चाहिए जिस से पेयजल की आपूर्ति में रुकावट न आए । साथ ही सरकार को चाहिए कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जीवनोपार्जन के लिए विशेष सहायता दे, शिक्षा एवं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता का प्रावधान करे । मैडम, हमारे मुख्य मंत्री जी बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं । अब दो दिन से इंदिरा गांधी नहर का पानी भी सूख गया है ।

मैडम, आप ने हमें बोलने का मौका दिया इस के लिए आप का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

Awareness programmes on environmental protection

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Madam, I rise to mention the enormous problems which arise on account of anti-environment activities, and the callous attitude of the Government in preventing them. We are all aware of the problem of water scarcity in the country. This problem has become an integral part of our life for years now; especially, the level of the underground water is going down and down. Before it gets exhausted, we should revive it; otherwise, the consequences might prove very grave. Severe deforestation has been taking place for decades resulting in environment imbalance, huge shortfall of rain, rise in temperature levels, etc. Unending usage of polythene, insufficient afforestation programmes, ever-growing population, industrial waste disposal through